Title: Regarding considerable reduction in the amount allocated for the Central Government sponsored projects for rural development in Bihar and other states.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सभी सांसदों को ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं को देखने के लिए जिला निगरानी समितियों का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया है। सभी पार्टियों ने इसको अच्छा कदम माना। लेकिन एक तरफ सभी सांसदों को निगरानी समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिया और दूसरी तरफ इंदिरा आवास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना और स्वर्ण जयन्ती स्वरोज़गार योजना और पीने के पानी की योजना में 800 रुपये की कटौती की गई है। राम विलास पासवान जी चले गए। वे वैशाली जिला के अध्यक्ष हैं। वहां 7 करोड़ रुपये संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना में कटौती हुई। इसी तरह से सरकार दावा करती है कि हम ग्रामीण विकास पर ज़ोर दे रहे हैं,बजट का प्रावधान भी दिया है और दूसरी तरफ कटौती की जा रही है। देखा जाए तो बिहार में 300 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। पश्चिम बंगाल में करीब 85 करोड़ रुपये की कटौती की गई। उत्तर प्रदेश में 69 करोड़ रुपये की कटौती की गई।

महोदय, इसका मतलब यह है कि इस तरह से कोई राज्य ऐसा बाकी नहीं है, पांच-छः राज्यों को छोड़कर कि जिनके पैसे की कटौती नहीं की गई हो। झारखंड के एक माननीय सदस्य यहां बोल रहे थे, उन्हें जानकारी भी नहीं होगी कि उनके राज्य की इंदिरा आवास योजना में 41 करोड़ रुपए, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में 33 करोड़ रुपए और फिर 38 करोड़ रुपए, फिर 9 करोड़ रुपए, फिर 11 करोड़ रुपए की कटौती की गई है।

श्री सुरेश रामराव जाधव : बिहार में खर्च नहीं हुआ, इसलिए कटौती की गई है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : खर्च कैसे नहीं हुआ, मैं बताता हूं।

अध्यक्ष महोदय : डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप अपनी बात बोलिए। उन्हें नहीं मुझे संबोधित कर कर के बोलिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि महाराट्र का पैसा भी काटा गया है। जवाहर रोजगार योजना के 9.68 करोड़, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के 3.83 करोड़ काटे गए हैं। इस तरह से कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसका पैसा नहीं काटा गया हो।

महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में मुजफ्फरपुर और वैशाली दो क्षेत्र हैं, जिनके बारे में मुझे जानकारी है। वहां सभी औपचारिकताएं 31 मार्च, 2003 के पहले पूरी कर दी गईं और सभी कागजात जमा करा दिए गए, लेकिन कोई न कोई पेंच लगाकर पैसा काट दिया गया। यह धन राज्य सरकार को नहीं जाता है। यह पैसा सीधा डी.आर.डी.ए. के अन्तर्गत प्रखंड में आता है, लेकिन वह पैसा नहीं दिया गया। एक दूसरी बात यह है कि यदि किसी एक डी.आर.डी.ए. की परफॉरमेंस खराब है, तो उसी राज्य के किसी दूसरे डी.आर.डी.ए. को वह पैसा दिया जाना चाहिए, लेकिन राज्य के बाहर किसी भी हालत में वह पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। मान लीजिए किसी एक डी.आर.डी.ए. का काम ठीक नहीं है, तो क्या पूरे राज्य के सभी डी.आर.डी.ए. का काम खराब हो जाएगा ? ऐसा नहीं है और न ऐसा होना चाहिए। इसलिए मेरा नि वेदन है कि एक राज्य का पैसा काटकर दूसरे राज्य को नहीं दिया जाना चाहिए।

महोदय, एक राज्य के पैसे को काटकर दूसरे राज्य को यदि दिया जाएगा, तो इससे रीजनल इम्बैलेंस पैदा होगा और रीजनील डिस्पैरिटी बढ़ेगी। इससे जिस राज्य का पैसा काटा जा रहा है उस राज्य के गरीबों का अहित होगा, क्योंकि इसमें इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत गरीबों को घर बनाने हेतु धन मिलता है। मेरा निवेदन है कि इसको दिखवा लीजिए और किसी भी राज्य की हिस्सेमारी न की जाए, ऐसी व्यवस्था कीजिए।

महोदय, सचिवालय में धन आबंटन के समय रुपए-पैसे भी चलते हैं। उसी के आधार पर आबंटन होता है। इसलिए सरकार इसका उत्तर दे। ग्रामीण विकास की जो ये योजानाएं हैं, इन सबसे गरीबी उन्मूलन की दिशा में प्रगति होती है। यदि इसके अन्तर्गत धन की कटौती की जाएगी, तो यह गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसलिए महोदय, मैं इस बारे में ध्यानार्काण प्रस्ताव दूंगा। इससे लोक सभा के सभी सदस्य कलंकित होंगे क्योंकि उनके रहते हुए गरीबों के उत्थान की योजनाओं के अन्तर्गत दिए जाने वाले धन की कटौती की जा रही है। इसमें सभी शामिल हैं। किसी को अध्यक्ष बना दिया, किसी को उपाध्यक्ष, लेकिन वे जनता को जाकर क्या मुंह दिखाएंगे कि उनके विकास हेतु दिए जाने वाले धन की कटौती भारत सरकार द्वारा क्यों की गई। इसलिए यह सवाल बहुत गम्भीर सवाल है और सभी सदस्यों, सभी जिलों और क्षेत्रों से संबंधित है। भारत सरकार राज्यों के धन की हिस्सेमारी कर रही है। राज्यों के हिसाब को ठीक ढंग से देखा जाए। ग्रामीण विकास की योजनाओं में इस तरह से कटौती कर के गरीबों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, उसे बन्द किया जाए।